कंगना की 'आज़ादी' पर क्यों बरपा है हंगामा; 2014 से लूट और झूठ भी आजाद हैं

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

कंगना राणावत ने क्या ग़लत किया, कुछ भी तो नहीं। मोदी-शाह के इशारों पर नाचने व भौंकने के बदले जिसे वाइ एक्स की सुरक्षा मिले, राष्ट्र का बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिले तो जिस हद तक भी संघी भाजपाई चाहें स्वतंत्रता सेनानियों को गालियां देने में हर्ज ही क्या है? अभी तो उसने केवल 2014 में आज़ादी की जुमलेबाज़ी की है। यदि वह कह दे कि सृष्टि का रचना ही नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बन कर खुद अपने हाथों से की है तो कोई उसका क्या कर लेगा?

दरअसल 12 वीं तक पढी कंगना जब भी और जो कुछ भी बोलती है वह अपने से नहीं बोलती, वह तो बेचारी उस तोते के समान है जिसे खुद नहीं पता होता कि जो वह बोल रहा है, उसका मतलब क्या है? संघी 'विद्वान' जिनका तथ्यों से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं, जो कुछ कंगना को रटा देते हैं वह उगल देती है। सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि मई 2014 में जिस दिन मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस दिन आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा था कि 700 सालों के बाद अब हिन्दू राष्ट्र की अपनी सरकार आई है। यानी कि अब तक जो सरकारें चलती रहीं खासकर 15 अगस्त 1967 से, वे इस राष्ट्र के लोग़ों की नहीं

थी। इसके अलावा भागवत किस आधार पर देश को हिन्दू राष्ट्र की संज्ञा दे रहे थे, यह सवाल अलग से है।

आज़ादी एक सब्जेक्टिव अवधारणा हो सकती है। 1947 से पहले अंग्रेजों को इस देश पर हुकूमत करने, अत्याचार करने व लूटने की पूरी आज़ादी थी। उनके जाने के बाद यह आज़ादी कांग्रेसियों को मिल गयी तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के बने कानूनों का भरभूर इस्तेमाल करते हुए जनता को जी भर कर लूटा, इतना ही नहीं अंग्रेज़ों को लूट का हिस्सा उन्हें घर बैठे पहुंचाते रहे जो आज भी जारी हैं। कांग्रेसियों की एकछत्र लूट की जब इन्तहा हो गयी तो विभिन्न राजनीतिक लुटेरों ने अपने-अपने ढंग से मोर्चेबंदी करके लूट के अवसर अपने लिये भी हथियाये।

मई 2014 में आरएसएस ने अपने प्रचारकों के माध्यम से लगभग पूरे देश में लूट का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसी अधिकार को कंगना आज़ादी बता रही है तो क्या ग़लत कह रही है? संघ के पालतू गुंडे जिसके ऊपर जो चाहे आरोप लगा कर उसकी हत्या कर दें। कोई उन्हें रोकेगा नहीं क्योंकि उन्हें ऐसा करने की आज़ादी मिली है। उन्हें पूरी आज़ादी है जिसका चाहें घर, दुकान, मंदिर मस्जिद आदि तोड़ दें जला दें, उन्हें कोई रोके टोकेगा नहीं। कंगना, अनुराग ठाकुर प्रवेश साहब सिंह व मिश्रा जैसे भौंपू जो चाहे अनर्गल एवं जहरीला प्रचार करें, उन्हें पूरी आज़ादी है न केवल आज़ादी बल्कि सुरक्षा के लिये पुलिस बल भी उन्हें दे रखा है, वरना जनता मार-मार के इनका भुरता बना दे।

वैसे एक और महत्वपूर्ण बात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि यह सब बोलने में कंगना पर कितना ज़ोर पड़ा होगा, उसकी क्या व्यक्तिगत मजबूरियां रही होंगी जो उसको यह सब बोल कर अपनी फ़जीहत करानी पड़ रही हैं। बेशक वह 12 वीं तक पढ़ी हैं लेकिन वे खुद बता चुकी हैं कि पर दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनके कोटे से किसी शिक्षण संस्थान में कंगना को आरक्षित सीट भी मिली थी। इसी बदौलत दादा हिमाचल विधानसभा में तीन बार कांग्रसी विधायक रहे हैं। तो क्या कंगना यह नहीं जानती-समझती कि भारत को अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद ही तो उसके दादा को स्वतंत्रता सेनानी का खिताब व विधायक बनने का मौका मिला था।

कोविड जनित वैश्विक तबाही में भी धन कुबेरों की पौ बारह

सबका साथ सबका विकास का कुत्सित सच जिस पर चर्चा होनी चाहिए

रवींद्र गोयल

(पिछले साल अदानी ग्रुप के मालिकन 1002 करोड़ रुपये रोज कमाकर यानी 42 करोड़ रुपये प्रति घंटा कमाकर भारत के दुसरे नंबर के अमीर कैसे बन गये। पिछले साल उसकी संपत्ति 261 प्रतिशत बढ़ कर 505900 करोड़ रुपये हो गयी है।)

'हुरून रिपोर्ट' लन्दन आधारित एक शोध और प्रकाशन संस्था है जो दुनिया के धन कुबेरों की संपत्ति, उसमें फेर बदल, उनके कामों आदी पर सालाना रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यूँ तो यह संस्था पुरानी है पर भारत में यह संस्था 2012 से काम कर रही है और सितेम्बर माह के अंत में इस संस्था ने 2020 के मुकाबले 2021 में भारत के धनपतियों की सूची और पिछले एक साल में उनमें आये बदलाव सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट बताती है की पिछले साल अदानी ग्रुप के मालिकन 1002 करोड़ रुपये रोज कमाकर यानि 42 करोड़ रुपये प्रति घंटा कमाकर भारत के दूसरे नंबर के अमीर बन गये है। पिछले साल उसकी संपत्ति 261 प्रतिशत बढ़कर 505900 करोड़ रुपये हो गयी है। मुकेश अम्बानी भारत का सबसे धनी आदमी है जिसकी संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपये जोड़ी गयी है। कोविद की दवा,कोवीशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टिट्यूट के मालिक पूनावाला परिवार 190 करोड़ रुपये प्रतिदिन कमा कर भारत के छटे नंबर का अमीर है। उनकी संपत्ति अब 1,63,700 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल भारत में 279 डॉलर अरबपति हैं। यानि जिनकी संपत्ति करीबन 7500 करोड़ रुपये से ऊपर है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में 1007 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से ऊपर है। और रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस सालों में इन धनी व्यक्तियों ने समग्रता में 2020 करोड़ रुपये रोज के हिसाब से धन कमाया है। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि कोविद की वैश्विक तबाही के दौर में दुनिया के धनपतियों ने भी अपने भारतीय बिरादरों की ही तरह बेतहाशा धन कमाया है।

आम आबादी को, अस्सी के दशक से जारी नवउदारवादी नीतियों के, पिछले कई सालों के तुजुर्बे ने साफ कर दिया था की उसके कल्याण हेतु बढ़ता विकास और टपक बूँद सिद्धांत (theory of trickledown) का अर्थशास्त्र कितना बोदा है. यह जनता के साथ धोखा है उनके जागरूक तबकों को गुमराह करने का षडयंत्र है। भारत में विकास की ऊंची दर का फायदा केवल उपरी तबके या मध्यम वर्ग के एक छोटे से तबके को ही मिला था। ज्यादातर लोग अपने को ठगा ही महसूस कर रहे थे।

लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह आश्चर्यजनक है कि आखिर कोविद जनित वैश्विक तबाही के बीच में भी इन धन्ना सेठों को बेतहाशा धन कमाने के अवसर कहाँ से मिल गए। सरकारी आंकड़े बताते हैं की 20-21में भारत की राष्ट्रीय आय 7.3 प्रतिशत से गिरी। लोगों का अपना तुर्जुबा भी बताता है कि उनको तो तबाही,बर्बादी का मुख देखना पड़ा है। अप्रैल 2020 के सरकारी बंदी के फरमान के बाद करोड़ों की तादाद में उन्हें पैदल ही घर जाना पड़ा है। राह में कितने भूखे प्यासे मर गए उसका कोई हिसाब ही नहीं। मोदी सरकार ने यह कहकर मदद करने से हाथ खींच लिए की उसके पास पैसे ही नहीं है। बहुत से लोग इस तर्क से सहमत भी लगते हैं। न सरकार अमीर लोगों पर टैक्स लगाना चाहती है और बहुत से लोग इस नीति को ठीक ही समझते हैं। नतीजा कोविद आबादी के बहुत बड़े हिस्से की तबाही का सबब बना है।

तब यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक ही है कि आखिर इस विपत्ति काल में धन कुबेरों की संपत्ति का अम्बार कैसे लग गया। उनके लिए उलटी गंगा कैसे बह रही है। कुछ लोग इसे किस्मत का खेल मान सकते हैं। पर मामला इतना सीधा नहीं है। बढती बेरोजगारी, घटती छोटे और मंझोले व्यक्तियों की आय के बीच चल रहे इस गोरख धंधे को समझने के लिए हमें उन्ही नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के सार को समझना पड़ेगा जो सामान्य हालात में धनियों को फायदा पहुंचता है। और धनी बनता है। नव उदारवादी नीतियों का सिद्धांत वाक्य है की विकास ही किसी समाज की भलाई की कुंजी है और उसके लिए वो सब किया जाना चाहिए जो धनपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करे-उनको सस्ते ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराओ, उनको सरकारी संपत्ति सस्ते में बेचो। कर में रियायत दो। कानून में छूट दो, सरकारी देनदारियों में रियायत दो। ताकि वो विकास को आगे बढ़ाये।

कोविद तबाही के बीच भी दुनिया की सरकारों की नजर इस मंत्र को ही लागू करने पर लगी हुई थी। भारत कोई इसका अपवाद नहीं था। ब्याज दर को कम से कम रखा गया। बड़े उद्योगपतियों को इस आधार पर की उनकी बिक्री कम है उन्हें सस्ते दर पर दिया गया। इन दोनों से मिलकर उनके पास नकद धन का भंडार जमा हुआ इस धन भंडार को उसने अपने से कमजोर इकाइयों की संपत्ति हड़पने में, सरकारी संपत्ति को सस्ते दाम में खरीदने में, सट्टे और शेयर बाजार में लगाया। तबाही के बीच शेयर बाजार झूमने लगा और धनपतियों की संपत्ति अनाप शनाप दर से बढ़ने लगी।

आम जनता की गरीबी और सेठों के धन में बढोत्तरी कोई पहली बार नहीं हो रही है। 2007/8 के अमरीकी 'सब प्राइम क्राइसिस' के दौर में भी यही देखा गया था। अपने विशाल निवेश और क्रय शक्ति के साथ, अरबपतियों के पास आर्थिक

उथल-पुथल के दौरान लाभ के लिए अपने स्वयं के संसाधनों के अलावा सरकारी संसाधन भी हैं। और उन के अनुकूल कर कानून और उसकी कमियां इनको भरपूर पैसा बटोरने के अवसर देते हैं।

संक्षेप में कहा जाए तो जबतक नवउदारवादी आर्थिक नीतियों और आम आदमी के कल्याण के नाम पर उच्च विकास की दर और टपक बूँद सिद्धांत के आर्थिक षडयंत्र से मुक्ति नहीं पाई जाएगी यह सिलसिला जारी रहेगा। यदि इससे मुक्ति पानी है तो आर्थिक संयोजन के ताने बाने को 'व्यापर करने की आसानी' (ease of doing business) से हटाकर 'जीने की आसानी' (ease of living) के अनुसार ढालना होगा। सरकार को 'लोगों के ऊपर मुनाफे को वरीयता' देने के चिंतन को उलटकर 'मुनाफे के ऊपर आम आदमी को वरीयता' की सोच पर चलना होगा। इसके लिए जरूरी है कि एक सीमा से ज्यादा संपत्ति के मालिकों पर संपत्ति कर, धनी तबके पर उच्च कर आदि द्वारा पोषित जनउपयोगी जरूरतों जैसे सिंचाई, अस्पताल और विद्यालय भवनों का निर्माण, जन परिवहन सेवाएँ आदि पर सार्वजनिक निवेश तथा सबको स्तरीय शिक्षा, स्वस्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकारी खर्च करना होगा।